नईदुनिया

हमलों से दहला दक्षिणी ईरान, बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास शक्तिशाली विस्फोट

तेहरान/वाशिंगटन

होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी वर्चस्व की लड़ाई से खाड़ी देशों तक बारूदी सुरंग फैल चुकी है। भीषण संग्राम के बीच ईरान का बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र धमाकों से दहल उठा है। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर हुए ताजा हमलों में हाथ होने से इनकार किया है। इससे पहले 28 फरवरी को अमेरिका-इजराइल की एकीकृत सैन्य कार्रवाई के ठीक एक माह बाद 28 मार्च को ईरान के इस संयंत्र को निशाना बनाया जा चुका है। ईरान का यह एकमात्र और पहला चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह फारस की खाड़ी के तट पर दक्षिणी ईरान के बुशहर शहर के पास स्थित है। हालिया संघर्ष के दौरान इसके आसपास के क्षेत्रों में मिसाइलें और प्रोजेक्टाइल गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। इसे 1970 के दशक में जर्मन कंपनियों ने बनाना शुरू किया था। बाद में इसे रूस के सहयोग से पूरा किया गया। यहां का पहला रिएक्टर (यूनिट-1) लगभग 1000 मेगावाट बिजली राष्ट्रीय ग्रिड को प्रदान करता है। ताजा विस्फोट से व्यापक रेडियोधर्मी रिसाव का खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिणी ईरान के रणनीतिक इलाकों में एक के बाद एक कई जोरदार धमाकों ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। स्थानीय मीडिया और ईरानी अधिकारियों का दावा है कि बुशहर संयंत्र के बेहद नजदीकी सुरक्षा घेरे के साथ चोगादक सैन्य अड्डे और तटीय इलाकों को निशाना बनाया गया है। अब तक किसी ने भी इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। ना ही ईरान ने किसी पर आरोप मढ़ा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि वाशिंगटन हर हाल में ईरान के साथ बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है। तेहरान के साथ तकनीकी बातचीत जारी है। रपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका ने गुरुवार को हालात को शांत करने की कोशिश की। परमाणु समझौते तक पहुंचने के लिए तकनीकी स्तर की बातचीत जारी है। मध्यस्थों ने बुधवार को ईरान और अमेरिका के नेतृत्व से फोन पर बातचीत भी की। इस समय दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने पर सहमति बनाने और फिर तकनीकी टीमों के बीच बातचीत के अगले दौर के लिए तारीख तय करने के लिए बड़े पैमाने पर कूटनीतिक कोशिशें की जा रही हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व अमेरिकी मरीन कार्प्स अधिकारी डैन ग्रेजियर का कहना है कि इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ होने की पूरी संभावना है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थानीय समयानुसार गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी कदमों के बारे में जानकारी दी।

न्यूज ब्रीफ

पहले डील फिर धमकी और अब अटैक, क्यों भड़के ट्रंप

वाशिंगटन। ईरान ने स्ट्रेट आफ होर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया, और इसके जवाब में अमेरिका ने 80 से अधिक सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें बरसाने का दावा किया। पहली नजर में यह संघर्ष विराम तोड़ने पर अमेरिका की सीधी सैन्य प्रतिक्रिया लगती है, लेकिन इस कहानी का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू भी है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। डोनाल्ड ट्रंप ने जून में जिस संघर्ष विराम और समझौते को अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बताया था, वही समझौता कुछ ही दिनों बाद उनके लिए राजनीतिक बोझ बन गया। उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के कई बड़े नेताओं ने सवाल उठाए कि आखिर अमेरिका ने ईरान को इतनी रियायतें क्यों दीं। इस डील के तहत अमेरिका ने होर्मुज से नौसैनिक नाकाबंदी हटाने और ईरानी तेल पर अस्थायी राहत देने जैसी रियायतें दीं। बदले में ईरान ने स्ट्रेट आफ होर्मुज खोलने का वादा किया। लेकिन इस डील के आलोचकों का कहना था कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता या प्राक्सी नेटवर्क पर कोई ठोस कार्रवाई करने का वादा नहीं किया। इसने ही ट्रंप के लिए राजनीतिक मुश्किलें पैदा कर दीं। टाम काटन, रोजर विकर, बिल कैसिडी, जान कार्निन और टेड क्रूज जैसे रिपब्लिकन नेताओं ने अलग-अलग शब्दों में इस समझौते पर सवाल उठाए। कुछ ने इसे अमेरिका की कमजोर सौदेबाजी बताया तो कुछ ने इसे अमेरिकी विदेश नीति का ब्लंडर कहा। वहीं कुछ ने कहा कि ईरान को बिना पर्याप्त कीमत चुकाए बड़ी राहत मिल गई। फिर 6-7 जुलाई को ईरान ने स्ट्रेट आफ होर्मुज में तीन वाणिज्यिक जहाजों पर हमला कर दिया। इससे ट्रंप को न केवल सैन्य जवाब देने का कारण मिला, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी अपनी छवि बदलने का एक बड़ा मौका मिल गया। मेरी राय में यहीं से पूरी तस्वीर बदलती है।

भूकंप से कुछ सेकंड पहले अलर्ट भेज सकता है गूगल का ये फीचर

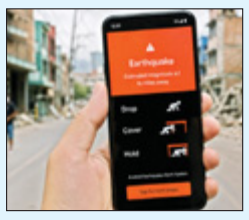

काराकास। प्राकृतिक आपदाओं के पूर्व सचेत करने को लेकर आधुनिक तकनीक ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ऐसा ही एक गूगल का एंड्रायड भूकंप अलर्ट फीचर है जो भूकंप के झटके महसूस होने से कुछ सेकंड पहले लोगों के मोबाइल फोन पर चेतावनी भेज सकता है। वेनेजुएला में हाल के दिनों में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद इस तकनीक की फिर से चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया कि भूकंप के झटके आने से पहले उनके एंड्रायड फोन पर गूगल की ओर से चेतावनी संदेश प्राप्त हुआ था। साझा किए गए स्क्रीनशाट के अनुसार, अलर्ट में संभावित भूकंप की तीव्रता, दूरी और आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी गई थी। इससे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सेकंड मिल सके। गूगल का यह सिस्टम पारंपरिक भूकंप मापने वाले उपकरणों के साथ-साथ दुनिया भर में मौजूद करोड़ों एंड्रायड स्मार्टफोन का भी उपयोग करता है। आधुनिक स्मार्टफोन में लगा एक्सेलेरोमीटर सेंसर फोन की गति और कंपन को पहचानने में सक्षम होता है। यही सेंसर सामान्य उपयोग के दौरान स्क्रीन को घुमाने या गतिविधियों का पता लगाने का काम करता है। जब किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्मार्टफोन एक जैसी असामान्य कंपन दर्ज करते हैं, तो यह जानकारी गूगल के सर्वर तक पहुंचती है। इसके बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता और विशेष एल्गोरिद्म यह विश्लेषण करते हैं कि कंपन किसी भूकंप के कारण है या सामान्य गतिविधि के कारण।

दुनिया के सबसे वीआईपी फोन नंबर्स का अनमोल संग्रह, मालिक के नाम दर्ज हैं 4 गिनीज रिकार्ड!

बीजिंग। एक गुमनाम शख्स ने मोबाइल नंबर याद रखने की आम परेशानी को एक अनोखे जुनून में बदल दिया, जिसने शख्स को सीधा गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स की किताब में पहुंचा दिया है। ये शख्स दुनिया के 15 सबसे दुर्लभ और वीआईपी मोबाइल नंबर्स के संग्रह के मालिक हैं, जिसे उन्होंने गोल्डन डिजिट्स नाम दिया है। इस अनमोल कलेक्शन में शामिल चार नंबरों ने गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स में अपनी जगह बनाई है, जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी करीब असंभव है। इस अनोखे शौक की शुरुआत करीब 15 साल पहले एक इत्तेफाक से हुई। जब उनका मोबाइल फोन खराब हुआ और उन्हें अपना ही नंबर याद करने में पसीने छूट गए, तब एक दोस्त ने सलाह दी कि उन्हें ऐसा नंबर लेना चाहिए, जिस याद रखना बच्चों का खेल हो। बस फिर क्या था, इस सलाह ने एक इसतरह के सफर की शुरुआत की, जिसने इस शख्स को वीआईपी नंबर्स का सबसे बड़ा कलेक्टर बना दिया। उन्होंने बार-बार दोहराए जाने वाले या पैटर्न वाले अंकों वाले नंबर्स को प्राथमिकता दी।

बांग्लादेश ने स्टारलिंक को दी बैंडविड्थ निर्यात की अनुमति नेपाल के लिए सैटेलाइट इंटरनेट का नया रास्ता खुला

काठमांडू

बांग्लादेश ने अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को दक्षिण एशियाई देशों के लिए बैंडविड्थ निर्यात करने की औपचारिक अनुमति दे दी है। बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग (बीटीआरसी) ने स्टारलिंक को अपने दूरसंचार ढांचे का उपयोग कर सीमा पार इंटरनेट ट्रैफिक भेजने की स्वीकृति प्रदान की है। इस फैसले के बाद नेपाल और भूटान जैसे स्थल-रुद्ध (लैंडलाक्ड) देशों के लिए बांग्लादेश सैटेलाइट इंटरनेट का प्रमुख ट्रांजिट हब बन सकता है। नई व्यवस्था के तहत स्टारलिंक बांग्लादेश की समुद्री सबमरीन केबल से प्राप्त अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ को सैटेलाइट के माध्यम से नेपाल तक पहुंचा सकेगा।

बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार के अनुसार, इस प्रक्रिया में बांग्लादेश बिना किसी अतिरिक्त फिल्टरिंग के बैंडविड्थ उपलब्ध कराएगा। बांग्लादेश के सैटेलाइट विशेषज्ञ और पुकु डाट एसएच के प्रबंध निदेशक मुस्तफा महमुद हुसैन का कहना है कि यदि नेपाल सरकार अनुमति देती है तो नेपाली उपभोक्ता आसानी से स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने इस व्यवस्था को विदेशी एंकर के साथ बेंट पाइप संरचना बताया।

उन्होंने कहा कि नेपाल में उपभोक्ता के घर पर लगे स्टारलिंक डिश (टर्मिनल) से लगभग 550 किलोमीटर ऊपर लो-अर्थ आर्बिट में मौजूद सैटेलाइट तक सिग्नल भेजा जाएगा। तकनीकी रूप से नेपाल में ग्राहक की डिश के अलावा किसी अतिरिक्त हार्डवेयर, गेटवे या सर्वर की आवश्यकता नहीं होगी।

ऐसे में बांग्लादेश को डेटा ट्रैम्पोलिन के रूप में उपयोग कर दक्षिण एशियाई बाजार में प्रवेश करने की रणनीति को एलन मस्क की बड़ी सफलता माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बांग्लादेश ने बैंडविड्थ निर्यात के बदले विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भी प्रभावी बातचीत की है।

स्टारलिंक लंबे समय से नेपाल में अपनी सेवा शुरू करने की इच्छा जता रहा है। हाल ही में कंपनी की निदेशक रेबेका हंटर काठमांडू पहुंचीं और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री विक्रम तिमिल्सिना से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नेपाल में इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति मांगी, लेकिन मौजूदा नीतिगत और कानूनी जटिलताओं के कारण अनुमति न मिलने की शिकायत भी की।

इससे पहले स्टारलिंक प्रमुख एलन मस्क ने तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ वर्चुअल बातचीत में माउंट एवरेस्ट (सगरमाथा) की चोटी तक स्टारलिंक सेवा पहुंचाने की इच्छा जताई थी। वहीं, पिछले कुछ वर्षों से नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों में स्टारलिंक इंटरनेट के अवैध उपयोग की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्याल के अनुसार, स्टारलिंक को नेपाल में सीधे ग्राहकों को सेवा देने के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण कर अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति वह न तो सीधे इंटरनेट सेवा बेच सकता है और न ही नेपाल की सीमा के भीतर सैटेलाइट सिग्नल का डाउनलिंक कर सकता है। हालांकि नेपाल के इंटरनेट सेवा प्रदाता किसी भी अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट दूरसंचार कंपनी से बैंडविड्थ खरीदकर अपने ग्राहकों को बेच सकते हैं। पौड्याल ने कहा कि किस देश या कंपनी से बैंडविड्थ खरीदनी है, यह पूरी तरह इंटरनेट सेवा प्रदाताओं का व्यावसायिक निर्णय है। सरकार इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। इसलिए बांग्लादेश का नया निर्णय नेपाली आपरेटरों के लिए एक अतिरिक्त विकल्प बन सकता है। वर्तमान में भी नेपाल के कुछ सेवा प्रदाता विदेशी सैटेलाइट कंपनियों से बैंडविड्थ खरीदकर इंटरनेट सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए अब तक दो कंपनियों को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस (जीएमपीसीएस) लाइसेंस मिला है। सानेपा स्थित कन्स्टिलेसन प्रा.लि. और कमलादी की आईफोर टेक्नोलाजीज ने यह लाइसेंस प्राप्त किया है। कन्स्टिलेसन 2022 से संयुक्त अरब अमीरात की थुरैया सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशंस से तथा आईफोर टेक्नोलाजीज ब्रिटेन की इनमारसैट से सैटेलाइट बैंडविड्थ लेकर नेपाल में इंटरनेट और सैटेलाइट फोन सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। कन्स्टिलेसन के सनातन गजुरेल का कहना है कि नेपाल के हिमालयी और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अवैध सैटेलाइट फोन और इंटरनेट के इस्तेमाल से उनका वैध कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उनके अनुसार, एवरेस्ट बेस कैंप-2 और बेस कैंप-3 में खुलेआम अवैध सैटेलाइट इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है। स्थानीय इंटरनेट सेवा प्रदाताओं का कहना है कि जब तक स्टारलिंक नेपाल में किसी स्थानीय कंपनी के साथ साझेदारी नहीं करता और आवश्यक लाइसेंस प्राप्त नहीं करता, तब तक वह यहां सेवा शुरू नहीं कर सकता। नेपाल की मौजूदा दूरसंचार नीति के अनुसार इंटरनेट सेवा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा 80 प्रतिशत है, जबकि शेष 20 प्रतिशत हिस्सेदारी स्थानीय साझेदार की होना अनिवार्य है। दूसरी ओर, स्टारलिंक अपनी कंपनी में 100 प्रतिशत विदेशी स्वामित्व बनाए रखने की शर्त पर अड़ा हुआ है। यही कारण है कि उसे अब तक नेपाल में व्यावसायिक अनुमति नहीं मिल सकी है। हालांकि, संचार मंत्री विक्रम तिमिल्सिना ने हाल ही में कहा था कि स्टारलिंक नेपाल के मौजूदा कानूनों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पंजीकरण करा सकता है।

भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 14 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भरेंगे उड़ान

वाशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 14 जुलाई को कजाखस्तान स्थित बैकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आठ महीने के मिशन पर रवाना होंगे। 49 वर्षीय मेनन भारतीय मूल के हैं। इस आशय की विज्ञप्ति नासा की वेबसाइट पर नौ जुलाई को साझा की गई है। विज्ञप्ति के अनुसार, मिनियापोलिस में यूक्रेनी और भारतीय प्रवासी माता-पिता के घर जन्मे मेनन आपातकालीन चिकित्सा के चिकित्सक और अमेरिकी अंतरिक्ष बल में कर्नल हैं।

नासा की विज्ञप्ति के अनुसार, अनिल मेनन, कास्मोनाट प्योत्र डुब्रोव और अन्ना किकिना के साथ रोस्कोस्मोस के सोयुज एमएस-29 स्पेसक्राफ्ट से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। वहां वे एक्सपीडिशन 74 क्रू के साथ मिलकर वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाएंगे। उत्तरी अमेरिका के समयानुसार तीनों सुबह 10:47 बजे (बैकोनूर समय के अनुसार शाम 7:47 बजे) उड़ान भरेंगे। इसका लाइव कवरेज नासा, अमेजन प्राइम और नासा के यू-ट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगा। नासा ने साफ किया है कि इस कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है।

अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन, डुब्रोव और किकिना अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटने से पहले अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक्सपीडिशन 74/75 क्रू सदस्यों के तौर पर आर्बिटल काम्प्लेक्स में लगभग आठ महीने बिताएंगे। मेनन की यह पहली, डुब्रोव और किकिना की यह दूसरी अंतरिक्ष उड़ान होगी। इस दौरान मेनन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने प्रवास के दौरान वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। इनमें लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का मानव शरीर पर पड़ने वाले शारीरिक प्रभावों का अध्ययन तथा यह जांच शामिल होगी।

संभल नहीं रहा देश तो भारत का नाम लेने लगा पाकिस्तान

इस्लामाबाद। पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं, आर्थिक संकट और बढ़ते उग्रवाद से जूझ रहा है, ऐसे में पाकिस्तानी सेना के डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी एक बार फिर अपनी नाकामियों का ठीकरा भारत पर फोड़ते नजर आए। अपनी फजीहत करवाने और सड़कछाप भाषा के लिए मशहूर इस जनरल ने अपनी सरकार और सेना की अक्षमता से ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए, जो पाकिस्तान में झूठ और छल की एक पुरानी आदत को दर्शाते हैं। देश में बार-बार सुरक्षा चूक, खुफिया विफलता और विद्रोह को रोकने में नाकामयाबी के कारण पाकिस्तानी सेना भारी दबाव में है, और ऐसे में भारत पर आरोप लगाना एक सुविधाजनक बहाना बन गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आटे, दाल और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों को लेकर जनता सड़कों पर है, बलूचिस्तान में बरसों के दमन से परेशान होकर बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के हमलों से दहल रहा है। इन गंभीर आंतरिक चुनौतियों के बावजूद, पाकिस्तानी नेतृत्व समाधान खोजने के बजाय भारत के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाने में व्यस्त है।

बुजुर्गों में स्मार्टफोन के कारण बढ़ सकता है डिप्रेशन का खतरा

बीजिंग

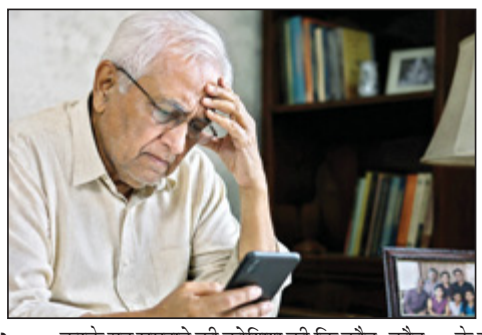

अगर स्मार्टफोन का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा या एक आदत के तौर पर किया जाए तो यह मानसिक स्वास्थ्य पर उल्टा असर भी डाल सकता है। हाल ही किए गए अध्ययन के अनुसार, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में इसके कारण डिप्रेशन (अवसाद) का खतरा काफी बढ़ सकता है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है।

यह महत्वपूर्ण अध्ययन रटगर्स स्कूल आफ सोशल वर्क के प्रोफेसर चिएन-चुंग हुआंग के नेतृत्व में किया गया और इसे प्रतिष्ठित जेएमआईआर एजिंग नाम की जर्नल में प्रकाशित किया गया है। शोध में चीन के ग्वांगझू शहर की 87 कम्युनिटीज में रहने वाले 2,585 बुजुर्ग लोगों को शामिल किया गया। इन लोगों से उनके स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की आदतों, उनके सामाजिक जीवन और उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की गई। इसके साथ ही, उनकी उम्र, शिक्षा का स्तर, आय और पारिवारिक स्थिति जैसे महत्वपूर्ण आंकड़े भी इकट्ठा किए गए। शोधकर्ताओं ने आधुनिक मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल करके यह समझने की कोशिश की कि कौन-कौन से कारण डिप्रेशन से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। इस विश्लेषण में सबसे बड़ा कारण कम सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना पाया गया, जिसका अर्थ है कि जो बुजुर्ग अपने सामाजिक दायरे से दूर रहते हैं, उनमें डिप्रेशन का खतरा ज्यादा होता है। इसके बाद स्मार्टफोन की लत या बहुत ज्यादा इस्तेमाल को दूसरा बड़ा कारण माना गया। जिन लोगों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा और आदतन पाया गया, उनमें डिप्रेशन के लक्षण भी ज्यादा देखे गए, जो इस तकनीक के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि फोन का इस्तेमाल हमेशा नुकसानदायक नहीं होता है। यदि बुजुर्ग लोग वीडियो काल, मैसेजिंग या फोटो शेयरिंग के जरिए अपने परिवार और दोस्तों से जुड़े रहते हैं तो यह उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह उन्हें अकेलापन महसूस करने से बचाता है और सामाजिक जुड़ाव बनाए रखने में मदद करता है। समस्या तब शुरू होती है जब फोन सिर्फ अकेले बैठकर वीडियो देखने, सोशल मीडिया पर स्क्राल करने या गेम खेलने का जरिया बन जाता है। इससे व्यक्ति धीरे-धीरे असल दुनिया के लोगों और गतिविधियों से दूरी बनाने लगता है, जिससे अकेलापन और अवसाद बढ़ सकता है। एक शोधकर्ता ने बताया कि जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपने फोन को वास्तविक सामाजिक जीवन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने लगता है तो यह डिप्रेशन का एक बड़ा संकेत हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि फोन ही बीमारी की वजह है, बल्कि यह कि फोन का गलत और अत्यधिक इस्तेमाल सामाजिक दूरी और अकेलेपन को बढ़ा सकता है। स्टडी में यह भी सामने आया कि कुछ खास समूहों में डिप्रेशन का खतरा ज्यादा देखा गया। जैसे वे बुजुर्ग पुरुष जिनकी शिक्षा कम थी और जो स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। इनके लिए डिजिटल दुनिया को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वे अक्सर सिर्फ मनोरंजन वाले कंटेंट पर निर्भर हो जाते हैं और धीरे-धीरे अकेलेपन में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, ज्यादा पढ़े-लिखे और अच्छे आर्थिक हालात वाले बुजुर्ग भी अगर फोन की लत में फंस जाते हैं तो उनके लिए भी अकेलापन और डिप्रेशन का खतरा बढ़ सकता है।

नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्रियों, पूर्व सेना प्रमुखों, पूर्व प्रधान न्यायाधीशों सहित 13,660 ने जमा कराया संपत्ति का विवरण

काठमांडू

सार्वजनिक पदों पर रहते हुए असामान्य रूपये से संपत्ति अर्जित करने के मामलों की जांच के लिए गठित संपत्ति जांच आयोग को अब तक 13,660 लोगों ने अपनी संपत्ति का विवरण सौंपा है। वहीं, कथित अवैध संपत्ति से जुड़ी 1,500 शिकायतें भी आयोग को प्राप्त हुई हैं।

आयोग के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्रियों, पूर्व प्रधान न्यायाधीशों, पूर्व सेना प्रमुखों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा कराया है। आयोग ने 14 अप्रैल को सार्वजनिक सूचना जारी कर जांच के दायरे में आने वाले पदाधिकारियों से एक महीने के भीतर अपने तथा अपने परिवार के नाम पर मौजूद संपत्तियों का विवरण जमा करने का आह्वान किया था। हालांकि अपेक्षित संख्या में विवरण नहीं मिलने पर आयोग ने समयसीमा बढ़ाकर 15 जुलाई के तक कर दी है।

अब तक पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल और सुशीला कार्की, पूर्व मंत्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्व उपप्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल, पूर्व मंत्री ओमप्रकाश अर्याल, रघुजी पंत, युवराज ज्ञवाली सहित कई वरिष्ठ नेताओं, पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, प्रकाशमान सिंह राउत तथा पूर्व प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटुवाल, मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल, अधिकांश सचिव, लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने संपत्ति विवरण जमा कराया है।

आयोग के प्रवक्ता गणेश केसी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन लगभग 500 लोग विवरण जमा करा रहे हैं। गुरुवार को आयोग को 660 संपत्तियों का विवरण प्राप्त हुआ। आयोग ने जांच के दायरे में आने वाले व्यक्तियों को आयोग में स्वयं उपस्थित होकर, डाक अथवा ई-मेल के माध्यम से भी संपत्ति विवरण जमा करने की सुविधा दी है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने मंत्रिपरिषद की बैठक में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय संपत्ति जांच आयोग के गठन का निर्णय लिया था। आयोग पहले चरण में वर्ष 2006 से लेकर 2026 मार्च तक सार्वजनिक पदों पर रहे पदाधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्तियों की जांच कर रहा है। इसके बाद वर्ष 1990 से 2006 तक सार्वजनिक पद संभालने वाले व्यक्तियों की संपत्तियों की जांच के लिए अलग से नई सूचना जारी की जाएगी।